

लोक प्रशासन (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

दो खण्डों में कुल आठ प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों की शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

PUBLIC ADMINISTRATION (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. इस प्रश्न के निम्नांकित सभी भागों का उत्तर दीजिए (प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) :

Attempt all of the following in about 150 words each :

10×5=50

- (a) “अधिकारीतंत्र के भीतर लोकतंत्र होने से उसकी प्रभावशीलता के कम हो जाने की संभावना रहती है।” क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

“Democracy within bureaucracy is likely to reduce its effectiveness.” Do you agree with this view? Argue your case.

- (b) “विकास की प्रक्रिया में जिला कलेक्टर की भूमिका पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

“District Collector’s role in the development process has been overemphasised.” Comment on the statement.

- (c) क्या कारण है कि जिला नियोजन को अनेक राज्यों में हाशिए (पृष्ठभूमि) में डाल दिया गया है, और वह केवल कुछ ही राज्यों में विशिष्ट स्थिति में रह गया है? समझाइए।

Why has District Planning been marginalised in many States and remained prominent in a few States? Explain.

- (d) “कार्यपालिका की अध्यादेश निकालने की शक्ति को उपयुक्त तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“Ordinance-making power of the Executive needs to be suitably restrained.” Examine it critically.

- (e) “‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ केवल एक नारा नहीं है, अपितु अपार संभावनाओं से युक्त प्रशासन का एक दर्शन है।” क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए।

“‘Minimum government, maximum governance’ is not just a slogan but a philosophy of administration with enormous potentialities.” Do you agree? Give reasons for your answer.

2. (a) राजनीतिक संस्कृति ने भारत की प्रशासनिक संस्कृति को किस सीमा तक प्रभावित किया है? समझाइए।

To what extent has political culture influenced the administrative culture of India? Explain.

20

- (b) भारतीय परिसंघीय तंत्र के रूपान्तरण के लिए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुंछी आयोग (2010) की मुख्य सिफारिशों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

Briefly discuss the main recommendations of the Punchhi Commission (2010) on Centre-State relations for transforming Indian Federal System.

20

- (c) जैसा कि डॉ० बी० आर० अम्बेदकर का कथन था कि “संविधान की विषयवस्तु राज्य के अवयव प्रदान कर सकती है किन्तु शासन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम इस पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दलों और जनता ने इसे किस तरह संचालित किया है”। इस कथन को सुस्पष्ट कीजिए।

As Dr. B. R. Ambedkar observed, “the text of the Constitution can provide the organs of the State, but the final outcome of the governance process depends on how it has operationalised by the political parties and people”. Elucidate the statement.

10

3. (a) ‘नीति’ आयोग के निर्णय-निर्माण के लिए उद्देश्यों, उपागमों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं का लक्ष्य भारतीय राजनीति के परिसंघीय चरित्र को पुनःप्रतिष्ठित करना है। स्पष्ट कीजिए।

The objectives, approaches and organisational arrangements for decision-making of the NITI Aayog aim at restoring the federal character of the Indian polity. Explain.

20

- (b) पूरी तरह स्पष्ट कीजिए कि भारत के सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता और जवाबदेयता में संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है।

Explain fully how a balance can be struck between autonomy and accountability of India’s public enterprises.

20

- (c) “यह आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत शासन सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में कार्य करें।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

“Decentralised governance must serve as an instrument of realising social change and social justice.” Comment on the statement.

10

4. (a) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 के पक्ष व विपक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए।

Discuss the arguments for and against the National Judicial Appointments Commission Act, 2014.

20

- (b) “बहुत हाल ही के वर्षों में राज्यों के राज्यपाल की भूमिका प्रशासनिक प्रकृति की होने की अपेक्षा कूटनीतिक अधिक होती दिखाई दी है।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

“In very recent time, the role of the State Governor is found to be more of diplomatic than administrative nature.” Comment on the statement with suitable examples.

20

- (c) संघ से राज्यों को उत्तरदायित्वों के न्यागमन (डेवोल्यूशन) और निधियों के स्थानांतरण के उपागम और प्रविधि में हुए अभिनव परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए।

Comment on the recent changes in the approach and methodology of devolution of responsibilities and transfer of funds from the Union to the States.

10

खण्ड—B / SECTION—B

5. इस प्रश्न के निम्नांकित सभी भागों का उत्तर दीजिए (प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) :

Attempt all of the following in about 150 words each :

10×5=50

(a) जनता और पुलिस के सम्बन्धों में सुधार के लिए, एक उपकरण के रूप में सामुदायिक पुलिसन की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the concept of community policing as a tool for improving public-police relations.

(b) समझाइए कि बजट का एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

Explain how budget can be used as a political instrument.

(c) “भारत में अधिकांश सिविल सेवक सक्षम प्रशासक हैं, किन्तु वे निर्णय-निर्माण में जन-सहभागिता के प्रोत्साहन की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

“Most Civil Servants in India are competent administrators, but they pay little attention to encourage people’s participation in decision-making.” Comment on the statement.

(d) क्या आप सोचते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं (पी० आर० आइ०) के वास्तविक कामकाज से शक्तियों और संसाधनों का यथार्थ न्यायमन परिलक्षित हो रहा है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए।

Do you think that the functioning of Panchayati Raj Institutions (PRIs), in practice, reflects genuine devolution of powers and resources? Give reasons for your answer.

(e) “सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइ० सी० टी०) से लोक सेवा संप्रदान की गुणता में तो सुधार होता है, किन्तु वह घूसखोरी को रोकने में असफल रहती है।” टिप्पणी कीजिए।

“Information Communication Technology (ICT) improves the quality of public service delivery, but fails to check bribery.” Comment.

6. (a) “भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् हुए प्रशासनिक सुधारों का अभिलक्षण उत्कृष्ट विचार किन्तु अपर्याप्त क्रियान्वयन रहा है।” संघ व राज्य सरकारों से उदाहरण देते हुए इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“Excellent ideas but poor implementation have characterised the administrative reforms in India since Independence.” Critically examine the statement giving examples from the Union and State Governments.

20

(b) क्या आप सहमत हैं कि भारत में विकास प्रशासन में एक गंभीर शासन-कमी रही है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण देते हुए सुझाव दीजिए।

Do you agree that there has been a serious governance-deficit in development administration in India? Give reasons for your answer and add your suggestions.

20

- (c) सिविल सेवा सुधारों के विषय में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख सरोकार क्या रहे हैं? उनके क्रियान्वयन की ताजा स्थिति बताइए।
What are the major concerns of the Second Administrative Reforms Commission on Civil Service reforms? Indicate the current status of their implementation. 10
7. (a) स्मार्ट एवं अमृत शहरों से सम्बन्धित संघ सरकार की नीतियाँ नगरीय विकास की प्रबन्धकीय समस्याओं को किस प्रकार सम्बोधित करती हैं? समझाइए।
How do the Union Government policies on Smart and AMRUT Cities address the problems of management of urban development? Explain. 20
- (b) कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा आन्तरिक विद्रोह और आतंकवाद का प्रतिकार करने में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के महत्त्व और भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the significance and role of the Central Paramilitary Forces in maintaining law and order and countering insurgency as well as terrorism. 20
- (c) केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों में समय-समय पर प्रवर्तित सुधारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा टिप्पणी कीजिए।
Discuss the major highlights of the reforms introduced from time-to-time in Central Civil Services Conduct Rules and add your own comments. 10
8. (a) “भारत का नगरीय शासन बारम्बार की प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है।” इस कथन को सुस्पष्ट करते हुए अपने सुझाव भी दीजिए।
“Municipal governance in India is not sufficiently prepared to meet the challenges of frequent natural disasters.” Elucidate the statement and add your own suggestions. 20
- (b) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन० आइ० ए०) के उद्देश्यों और क्षेत्राधिकार के विशिष्ट अभिलक्षणों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।
Discuss critically the salient features of the National Investigation Agency (NIA) regarding its purposes and jurisdiction. 20
- (c) भारत में मरणासन्न सार्वजनिक क्षेत्रक के वर्धन के लिए भारतीय लोक उद्यम तथा औद्योगिक सेवा के सृजन के पक्ष व विपक्ष के मुद्दे पर तर्क दीजिए।
Argue the case for and against creating Indian Public Enterprises and Industrial Service for boosting the moribund public sector in India. 10
